an>

Title: Regarding the decision of Executive Council of Jamia Millia Islamia University on reservation policy.

डॉ. उदित राज **(**उत्तर-पश्चिम दिल्ली**) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यहां उन लोगों की बात उठाने जा रहा हूं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। अगर रिजर्वेशन न होता तो आज भी इनकी हालत नारकीय होती। पोलिटिक्स और गवर्नमैंट जॉब्स में रिजर्वेशन होने की वजह से इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी एक नैशनल यूनीवर्सिटी है, लेकिन उसने वर्ष 2011 के एडमिशन में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। वर्ष 2014 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन लागू करने के लिए डिनाई किया। क्या जामिया यूनीवर्सिटी को कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट नहीं मिलती है? क्या टैक्स पेयर्स की मनी उन्हें नहीं जाती है? उन्होंने माइनोरिटी को रिजर्वेशन दिया, यह ठीक बात है। उन्होंने पीपल्स विद डिसएबिलिटीज, एनसीसी और तमाम केटेगिरीज के लोगों को रिजर्वेशन दिया है तो वहां क्यों एससी और एसटी के रिजर्वेशन को समाप्त किया गया है?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। पूरे देश में लेडीज यूनीवर्सिटी बहुत कम हैं। जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी अच्छी यूनीवर्सिटी है। वहां पहले उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता रहा है लेकिन अब क्या वजह है कि यह रिजर्वेशन डिसकन्टीन्यू हुआ है? मुझे यही पैटर्न अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी देखने को मिला है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।